रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**
**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)**
**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**
**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

| | |
|---|---|
| **सं. 1432]** | **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 18, 2019/चैत्र 28, 1941** |
| **No. 1432]** | **NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 18, 2019/CHAITRA 28, 1941** |


## श्रम और रोजगार मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2019

**का.आ. 1614 (अ).—**केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, कि बैंकिंग उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची के मद 2 के अधीन सम्मिलित हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक उपयोगी सेवा है ;

और केन्द्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 18 अक्तूबर, 2018 में अंतिमत: प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5326(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2018 उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए उक्त उद्योग 21 अक्तूबर, 2018 से छह मास के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में और छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा की स्थिति का विस्तार करना अपेक्षित है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंकिंग उद्योग में लगी हुई सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए तारीख 21 अप्रैल, 2019 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[फा. सं. एस-11017/5/97-आई.आर.(पी.एल.)]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2019

**S.O. 1614(E).—**Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Banking industry, which is covered under item 2 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 21st October, 2018 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.5326(E), dated the 18th October, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 18th October, 2018;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the Banking industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 21th April, 2019**.**

[F.No. S-11017/ 5/97- IR(PL)]

AJAY TEWARI**,** Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.04.18 18:45:22 +05'30'